

persons. You have read the names of other persons. What about these persons? Please let me know. I have written to you a letter, and I have the right to get a reply from you.

SHRI K BRAHMANANDA REDDY  
I shall look into it.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted

16.07 hrs.

#### PRESIDENT'S PENSION (AMENDMENT) BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI F. H. MOHSIN): I beg to  
move.\*

"That the Bill further to amend  
the President's Pension Act, 1951, be  
taken into consideration."

This is a very simple Bill. The existing provisions of the President's Pension Act, 1951, *inter alia*, provide for medical attendance and treatment, free of charge, to a retired President. But such facilities are not available to the spouse of a retired President or the spouse of a President who dies while holding office as such. Keeping in view the dignity of the high office of the President, it is proposed to extend the said facilities to the spouse of a President in both cases.

This is a very simple Bill and I commend it for the acceptance of the House.

16.08 hrs.

[SHRI P. PARTHASARATHY in the Chair]  
MR. CHAIRMAN Motion moved:

"That the Bill further to amend  
the President's Pension Act, 1951, be  
taken into consideration."

Sardar Swarn Singh Sokhi.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर)

चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस पर कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, उम्मीद है मिनिस्टर साहब उन का ख्याल करेंगे। प्रेसीडेंट पेंशन ऐक्ट 1951 में बना था और 15,000 रु० सालाना पेंशन प्रेसीडेंट की बाकी जिन्दगी के लिये रखी गई थी, तथा 12,000 रु० सालाना सेक्रेटेरियल स्टाफ के लिये था। आज उन ऐक्ट को बन 25 साल हो गये हैं लेकिन वह पेंशन उतनी की उतनी ही है। जब यह बिल आया तो मैं समझा कि शायद प्रेसीडेंट की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। जब आज सारी चीजों का दाम बढ़ गये तो प्रेसीडेंट की पेंशन भी बढ़ानी चाहिये। उस वक्त में 15,000 रु० सालाना आज कल 2,400 रु० सालाना के बराबर हैं। प्रेसीडेंट के रिटायर होने के बाद जो उन के खर्चे बड़े हुए होते हैं उन को कट डौन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिये इतने बड़े ग्रॉफिम को ध्यान में रखते हुए उन की पेंशन मेरी राय में कम से कम 25,000 रु० सालाना होनी चाहिये, और इसी तरह से सेक्रेटेरियल स्टाफ का खर्चा भी बढ़ाना चाहिये क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा समय आये जब पैसा न होने की वजह से रिटायर्ड प्रेसीडेंट को को

\*Moved with the recommendation of the President.

[सरकार स्वर्ण सिंह सीनियर]

तकलीफ हो। जब स्वीकर की, डिप्टी स्वीकर की तनकाहें बढ़ गई, मेम्बर आफ पार्लियामेंट के अलाउन्स बढ़ चुके हैं, उन को कांस्टीट्यू-एँसी अलाउन्स भी दिया गया है, तो आप मेहरबानी कर के प्रेसीडेंट की पेंशन को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिये।

इस बिल के द्वारा उन की स्वाउड को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था की जा रही है, जो एक अच्छी बात है। इस बारे में सरकार ने पहले से क्यों नहीं सोचा?

हमारे देश में मोहमेदन प्रजिडेंट भी होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रीजिडेंट आफिस में मर जाये, जिस के चार स्वाउस हैं, जो उन लोगों के लिए लीगली अलाउड है, उन सब के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। डा० जाकिर हुसैन साहब आफिस में रहते हुए मर गये। मेरे ब्याल में उन की बीबी को लाइफ-टाइम के लिए जरूर पेन्शन देनी चाहिए।

अमरीका में प्रीजिडेंट केनेडी आफिस में रहते हुए मर गये। वह दो बच्चे छोड़ गये, जो नाबालिग थे। उन बच्चों की देख-रेख के लिए मिसेज केनेडी को नई सारी करनी पड़ी। (अव्यवधान) सारी दुनिया को इस का पता है। मैंने अखबारों में पढ़ा है, मैं यह बता रहा हूँ। और हिन्दुस्तान में तो ऐसा नहीं होना। जो प्रीजिडेंट आफिस में रहते हुए मर जाते हैं मैं उन की बीबी को पेन्शन देने के बारे में कह रहा हूँ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री राजबख्शार साहनी (पटना) :

समापति बहोदय, इस बिल का मतलब केवल यही है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति की, या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जिन की मृत्यु हो जाये, उस की पत्नी को चिकित्सा की सुविधा दी जाये। कोई भी व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं कर सकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सरकार इस तरह की व्यवस्था भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की पत्नियों के लिए कर रही है, तो वह थोड़ा आगे भी जाये, और उस के जो कर्मचारी हैं, उन के लिए भी कुछ व्यवस्था करे और फिर हम लोग भी हैं।

श्री भूलचन्द डागा (पाली) : हम कर्मचारी नहीं हैं।

श्री राजबख्शार साहनी : हम जनता के कर्मचारी हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस विधेयक का विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन इस भावना को हम थोड़ा नीचे भी ले जाये और सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करें।

यह भी देखना चाहिए कि जिन लोगों को पेन्शन दी जाती है, क्या वह उन को समय पर मिलती है। राष्ट्रपति को तो जरूर समय पर मिलती हूँगी, लेकिन दूसरे लोगों को समय पर नहीं मिलती है। इस के अलावा इस समय जो पेन्शन मिलती है, वह कम है। सरकार मेन्डेट में कुछ वृद्धि की है, अगर उन में और वृद्धि करने की आवश्यकता है।

की सोची ने कहा है कि मूलपूर्व राष्ट्रपतियों की पेन्शन बढ़ानी चाहिए। उन का माथ ही यह भी कहना चाहिए था कि अन्य पण्डितों की पेन्शन की राशि भी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि महगार्ड वगैरह राष्ट्रपति के लिए नहीं है, महगार्ड उन मामलों के लिए भी है जो पेंशन पाते हैं। तो उन की पेन्शन की राशि भी बढ़ाए और समय पर उन को दीजिए ताकि वे महसूस करें कि सरकार उन का प्रति मजबूत है, मजबूत है, उन की कठिनाइयों को ध्यान में रखती है, उन की सेवाओं का बदला भुगत रही है, पूरा बदला तो आप नहीं भुगत सकते फिर भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। यद्यपि इस विधेयक का दायरा बहुत सीमित है लेकिन यह निवेदन मैं इस के संघ में आप में अवश्य करूँगा कि कर्मचारियों स्वतंत्रता सनानियों या दूसरे पेंशन पाने वाले लोग हैं उन की दशा पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। उन के लिए ठीक तरह से चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अभी चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था बहुत जगह नहीं होती है। सरकारी अस्पताल भी आप के हाते हैं ना कभी दवा नहीं होती है, कभी डाक्टर नहीं होते हैं, अभी सरकार अपना पैसा जी एच एन स्काम लागू करने जा रही है लेकिन बल तीव्र डिस्पेंसरीज बना रही है तो उस से क्या होगा। वहाँ हजारों हजार कर्मचारी हैं, 3 डिस्पेंसरीज से उन की सेवा कैसे कर सकेंगे? तो उस दृष्टिकोण को आप ध्यान में रखिए कि पर्याप्त मात्रा में आप की डिस्पेंसरीज हों डाक्टर हों, दवाएँ हों, नर्सज हों, पूरी व्यवस्था हो। ऐसा आप ने किया तब तो इस तरह

1291 L.B.

के बिल का कोई मतलब है। इन के लिए तो आप जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह की सुविधाएँ ओरो को भी दी जाएँ। उन के लिए ठीक तरह का व्यवस्था काज आए। इन गब्दा के साथ ही इन बिन्दु सनर्धन करता हूँ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) I am thankful to both the participants who have spoken on this Bill

As I have already said, it is a very simple Bill extending the facilities of medical assistance to the wives of the ex-Presidents or retired Presidents. This was not there in the original Bill. Only ex-Presidents were entitled to free medical assistance along with a pension of Rs. 15,000 per annum and also Rs. 12,000, per annum for maintenance of secretarial staff. Later on, it was found that their wives also should be given medical assistance in conformity with the practices elsewhere. That is why this Bill has been brought forward

Of course some other suggestions also have been made that even the pension should be raised, that the pension of Rs. 15,000 was fixed long time ago and it needs a revision. Of course, there is considerable point in what the hon. Member says. Even in respect of salaries of Ministers, they were fixed quite long time ago, but I am not advocating that. In this Bill the only intention is to extend the free medical assistance to the wives or widows of the former Presidents and to the spouses of future incumbents

SHRI RAMAVATAR SHASTRI has made—of course not quite relevant—a point in this connection, that the pension of other Government servants should also be raised

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Including Freedom Fighters,

SHRI F. H. MOHSIN: But that is a different scheme altogether.

[Shri F. H. Mohsin]

This cannot be tagged on to the Freedom Fighter's pension which has already been fixed. That is not relevant to the Bill before us. I can discuss it with him later.

I once again thank the hon. Members for their full support and I move that the Bill be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is—

"That the Bill further to amend the President's Pension Act, 1951, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: There are no amendments to clauses 2 to 4. I am putting them to the vote of the House.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI F. H. MOHSIN: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

SEYID MUHAMMAD: I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 be taken into consideration".

Article 82 of the Constitution provides that upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine. It further provides that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House. There is a similar provision in article 170(3) of the Constitution in respect of the Legislative Assemblies of the States. In accordance with these provisions of the Constitution Parliament enacted the Delimitation Act, 1972 providing for the setting up of a Delimitation Commission. The Delimitation Commission appointed under the Delimitation Act, 1972 has completed the work of final determination of the number and the extent of Parliamentary and Assembly constituencies in respect of all States and Union territories, except the Union territory of Arunachal Pradesh. Under the provisions of the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1975 the Election Commission has been entrusted with the task of determining the extent of the two Parliamentary constituencies and 30 Assembly constituencies in the Union territory of Arunachal Pradesh and the final orders of delimitation in this regard have also been issued.

The purpose of the amendments contained in the present Bill is to empower the Election Commission to consolidate all orders of delimitation into a single Order and to maintain the said Order up-to-date by correcting printing mistakes, etc. The First and the Second Schedules to the Representation of the People Act, 1950 are also being amend-

16.21 hrs.

# REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND  
COMPANY AFFAIRS (DR. V. A.